[2015] 12 एस. सी. आर. 661

याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन

बनाम

महाराष्ट्र राज्य, जरिये सचिव, गृह विभाग और अन्य

(2015 की रिट याचिका (आपराधिक) सं. 129)

29 जुलाई, 2015

[दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सी. पंत और

अमितावा रॉय, न्यायाधिपतिगण]

उच्चतम न्यायालय नियम, 2013:

आदेश XLVIII नियम, 4 (1) और (2)-1993 बॉम्बे बम विस्फोट-दोषसिद्धि और मृत्युदंड-फांसी रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मौत की सजा पर रोक-सवाल है कि क्या सुधारत्मक याचिका नियमों के अनुसार विधिवत रूप से गठित पीठ द्वारा निस्तारित की गई थी- माना गया:- न्यायपीठ में तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों को पक्षकार के रूप में होना आव्श्यक है और 'शिकायताधीन निर्णय' के न्यायाधीश पक्षकार होने चाहिये, और यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो अन्य न्यायाधीशों को शामिल करना

भारत के मुख्य न्यायाधीश का विवेकाधिकार है; लेकिन, यदि इसे तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा निपटा जाता है, जैसा कि इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ-सबसे अधिक न्यायाधीशों द्वारा, तो आदेश शून्य नहीं रहेगा।

आदेश XLVIII नियम 4 (1) और (2)- शिकायताधीन निर्णय - आदेश । नियम 2 (1) (के) केवल इसलिए कि पुनर्विचार याचिका के खारिज होने को 'निर्णय' के रूप में नामित किया गया है, यह 'शिकायताधीन निर्णय' की अवधारणा के दायरे और विस्तार के भीतर नहीं आएगा।

आदेश । नियम 2 (1) (के)- क्या 'आदेश' शब्द जो 'निर्णय' की परिभाषा एक हिस्सा है जैसा कि नीचे आदेश । नियम 2 (1) (के) में निर्धारित किया गया है, का अर्थ यह होगा कि समीक्षा में आदेश या मुख्य निर्णय में पारित निर्णय- आदेश । यह प्रधान निर्णय/मुख्य निर्णय है।

सजा/सजाः 1993 बम्बई बम विस्फोट दोषसिद्धि और मृत्युदंड - रिट याचिकाकर्ता द्वारा मृत्युदंड पर मांगी गई रोक- याचिकाकर्ता की याचिका प्रक्रियात्मक उल्लंघन था क्योंकि टाडा अदालत के रूप में ने 30.04.2015 को निष्पादन का निर्देश देते हुए 30.7.2015 को मृत्यु वारंट जारी किया गया था जबकि उपचारात्मक याचिका दायर की जानी बाकी थी - टाडा अदालत ने 90 दिनों का समय दिया फिर भी याचिकाकर्ता को केवल

13.07.2015 को सूचित किया गया जो लाइलाज प्रक्रियात्मक अवैधता से ग्रस्त है और मृत्यु वारंट को रद्द करने योग्य है- माना: इस मामले में, वारंट जारी होने के बाद, हालांकि यह याचिकाकर्ता को 13.07.2015 को जारी किया गया था, फिर भी उसने उपचारात्मक याचिका 22.05.2015 को दायर की थी और इसलिए, वह यह याचिका नहीं ले सकता है कि उसने कानूनी उपायों का लाभ नहीं उठाया था-उपचारात्मक याचिका 21.07.2015 को खारिज कर दी गई थी-याचिकाकर्ता ने दोषसिद्धि पर बचाव करने के लिए अवसरों की श्रृंखला का लाभ उठाया और पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के लिए दस दिन की पेशकश की गई थी - याचिकाकर्ता के भाई ने भारत के राष्ट्रपति के लिए दया याचिका दायर की थी- याचिकाकर्ता को इसका बिल्कुल ज्ञान था - उन्हें दया याचिका की अस्वीकृति के बारे में 11.04.2014 को विधिवत सूचित किया गया था - इस प्रकार जारी मृत्यु वारंट क्रम में था।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया।

1. जबकि यह न्यायालय एक उपचारात्मक याचिका के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, यह वास्तव में प्रधान निर्णय/मुख्य निर्णय है, जो विचाराधीन है। उक्त निर्णय मुख्य निर्णय है और वास्तव में एक मामले में दोषसिद्धि की अंतिमता संलग्न करता है और पुनःपरीक्षण एक अलग बात है। सुधारात्मक याचिका मुख्य निर्णय के विरुद्ध दायर की

गई जो कि वास्तव में शिकायताधीन है। तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों को स्पष्ट रूप से पीठ के समक्ष पक्षकारों के रूप में दर्शाया गया है और 'शिकायताधीन' न्यायाधीशों को पक्षकार होने के लिए कहा गया और यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो कुछ अन्य न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है ; हालाँकि, यदि यह तीन सबसे अधिक वरिष्ठ- न्यायाधीशों द्वारा निपटाया जाता है, जैसा कि इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सबसे अधिक वरिष्ठ- न्यायाधीशों द्वारा किया गया है, अतः आदेश अमान्य नहीं होगा। तत्काल मामले में, हालांकि, जिन न्यायाधीशों ने मुख्य निर्णय दिया था, वह स्वीकार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। यदि एक सिद्धांत के रूप में यह निर्धारित किया गया है कि वे न्यायाधीश जो उन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति जिन्होंने पद छोड़ दिया है, समीक्षा का निर्णय लेते हैं, तो वे न्यायिक अनिवार्यता द्वारा पक्षकार बनाए जाने हैं, जो उचित नहीं है। एक निर्णय को एक कानून के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए,बल्कि निश्चित रूप से एक निर्णय को उचित परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। केवल इसलिए कि बर्खास्तगी समीक्षा याचिका का नाम 'फैसला' रखा गया है, यह 'शिकायताधीन निर्णय' की अवधारणा के दायरे और स्वीप के भीतर नहीं आएगा। इस न्यायालय के तीनों वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा सुधारात्मक याचिका को खारिज करने को को सही माना जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक

अनियमितता से दूषित नहीं माना जाये। [पैरा 13 से 16] [675-ई-एफ; 676-बी-सी, ई-एफ; 677-ए, सी-डी]

2. याचिकाकर्ता पर टाडा अदालत के समक्ष विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था जिसने उस पर मौत की सजा सुनाई थी। अपील में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आरोपों, विभिन्न प्रस्तुतियों से सहमति जताई थे और अंततः टाडा कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सहमत हुए। 21 मार्च, 2013 को फैसला सुनाए जाने के बाद में, समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जो 30 जुलाई, 2013 को प्रचलन द्वारा खारिज कर दिया गया था। समीक्षा के लिए आवेदन की अस्वीकृति के बाद, याचिकाकर्ता के भाई ने संविधान के अनुच्छेद 72 (1) के तहत लाभ का दावा करते हुए, 6 अगस्त, 2013 को भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत अभ्यावेदन दिया। याचिकाकर्ता ने 7 अगस्त, 2013 को अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, नागपुर, को भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा याचिका की प्राप्ति के बारे में सूचित करते हुए पत्र लिखा। 2 सितंबर, 2013 को भारत सरकार ने दोषी की दया याचिका को प्रक्रिया के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 14 नवंबर, 2013 को अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया और 30 सितंबर, 2013 को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को राज्यपाल द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया। 10 मार्च, 2014 को राज्य सरकार से उक्त संचार की प्राप्ति पर, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की

गई मामले/दया याचिका का सारांश गृह मंत्री के हस्ताक्षर सहित भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया। 11 अप्रैल, 2014 को भारत के राष्ट्रपति ने याचिकाकर्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया।17/21.04.2014 को इस शर्त के साथ कि दोषी को सूचित किया जाए, उक्त अस्वीकृति राज्य सरकार को सूचित कर दी गई थी, और तदनुसार, 26 मई 2014 को, याचिकाकर्ता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया था। [पैरा 17 एंड 18] [677 - ई-एच; 678-ए-डी]

3. शबनम मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड वारंट जारी करने से पहले दोषी को पर्याप्त नोटिस दिया जाना है ताकि वह कार्यवाही में उसे अपने अधिवक्ताओं से परामर्श करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम करे। यह उद्देश्य होने के नाते, यह तथ्यों की वर्तमान व्याख्या में देखा जाना चाहिए। इस मामले में, वारंट जारी होने के बाद, हालांकि यह याचिकाकर्ता को 13.07.2015 जारी कर दिया गया था, फिर भी उसने 22.05.2015 को उपचारात्मक याचिका दायर की थी और इसलिए, वह यह दलील नहीं दे सकता है कि उन्होंने कानूनी उपायों का लाभ नहीं उठाया था। उपचारात्मक याचिका 21.07.2015 को खारिज कर दी गई थी। इस मामले में उक्त जनादेश के पीछे के उद्देश्य का पालन किया गया था। शत्रुघ्न चौहान के मामले में, अपील के खारिज हो जाने के बाद, वारंट छह दिन बाद जारी किया गया।

निस्संदेह, ऐसे मामले में यह किसी भी सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। वही सिद्धांत लागू होंगे लेकिन हस्तगत मामले में, उक्त सिद्धांतों को यह कहने के लिए नहीं खींचा जा सकता है कि प्रक्रिया के पहलुओं में से एक का गैर-अनुपालन नहीं होने के आधार पर टाडा न्यायालय द्वारा जारी वारंट अमान्य होगा। जिस तरह से याचिकाकर्ता ने दोषसिद्धि का बचाव करने के कई अवसरों का लाभ उठाया था और जैसा कि स्वीकार किया गया उन्हें दस दिनों की पेशकश की गई थी जब पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई हुई। [पैरा 28] [686-सी-एच]

4. एक दोषी, अपनी दोषसिद्धि के बाद, किसी भी स्तर पर, संवैधानिक प्राधिकारी के समक्ष क्षमा या माफी या अन्य राहत की मांग अभ्यावेदन कर सकता है जैसा कि उक्त अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया था। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता के भाई ने भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता को बिल्कुल इसकी जानकारी थी। उनसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपर्क किया गया था कि जो भारत के राष्ट्रपति के पास है 11.04.2014 को उसी को अस्वीकार कर दिया। पहली दया याचिका के खारिज हो जाने के बाद, उसे याचिकाकर्ता ने चुनौती नहीं दी। [पैरा 29,30] [687-सी-डी, जी-एच]

रूपा अशोक हुर्रा 2002 (40) एस. सी. सी. 388; सो चंद्र कांटे और अन्य बनाम शेख हबीब (1975) 1 एस. सी. सी. 674; मो. आरिफ

उर्फ अशफाक बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य (2014) 9 एससीसी 737 ; शत्रुघ्न चौहान और अन्य बनाम यूनियन ऑफ भारत और अन्य (2014) 3 एससीसी 1: 2014 (1) एससीआर 609; शबनम बनाम भारत संघ और अन्य 2015 (7) स्केल 1-पर भरोसा किया गया।

मामला कानून संदर्भ

2002 (40) एस. सी. सी. 388	पर भरोसा किया	पैरा 6
(1975) 1 एस. सी. सी. 674	पर भरोसा किया	पैरा 13
(2014) 9 एससीसी 737	पर भरोसा किया	पैरा 19
2014 (1) एससीआर 609	पर भरोसा किया	पैरा 23
2015 (7) स्केल 1	पर भरोसा किया	पैरा 23

मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (आपराधिक) सं. 129/2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

मुकुल रोहतगी, एजी, तुषार मेहता, एएसजी, राजू रामचंद्रन, टी.आर. अंध्यारुजिना, सुश्री विभा दत्ता माखीजा, वरिष्ठ एड., फैसल फारूक, शुबैल

फारूक, श्रीमती प्रिया पुरी, रंजय दुबे, सुश्री मैथिली विजय के. आर. थल्लम, विक्रम आदित्य नारायण, आलम मोहम्मद। इजहार, एम. पी. सिंह, निशांत आर. कटनेश्वरकर, श्रीमती देवांशी सिंह, गुरमेहर सिस्तानी, अर्पित राय, सुश्री रंजीता रोहतगी, सोमित खोसला, दीक्षा राय गोस्वामी, महालिंग पंडार्गे, सुश्री ज्योति कालरा, आनंद ग्रोवर, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, रवि चंद्र प्रकाश, सुश्री तृप्ति टंडन, सुश्री अमृता नंदा, चंद कुरैशी, अशोक कुमार जुनेजा, राहुल नारायण, निशांत गोखले, सुश्री श्रेया रस्तोगी, मोहित सिंह, शोमिक घोष, सिद्धार्थ सिरोजिया, बी. पी. सिंह, धाकरे, राजीव नंदा, बी. वी. बलराम दास और सुश्री दिशा वैश, अधिवक्ता , उपस्थित पार्टियों के लिए उनके साथ।

न्यायालय का निर्णय **दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति** द्वारा दिया गया था।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता, जिसे मौत की सजा सुनाई गई है, ने बॉम्बे विस्फोट मामले में टाडा (पी) अधिनियम, 1987 के तहत नामित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित 30 अप्रैल, 2015 का आदेश, और ग्रह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के आदेश संख्या-0113 / सी.आर./ 652/ सी.आर./ 652/ 13/ पी.आर.एस.-3 दिनांक 13 जुलाई, 2015 और अधीक्षक नागपुर केंद्रीय कारागार, नागपुर द्वारा जारी ओ. डब्ल्यू. No.ASJ/डेथ सेंटेन्स/ 222/2015 वाला संचार दिनांक 13 जुलाई,

2015 जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को दी गई मृत्यु सजा की 30 जुलाई, 2015 को सुबह 7 बजे अनुपालना का निर्देश दिया गया है, को रद्द करने के लिये एक मान्डमस या उपयुक्त रिट या निर्देश जारी करने, उत्तरदाताओं और उनमें से प्रत्येक को अपने अधीनस्थों/एजेंटों/नियुक्तियों के साथ 30 अप्रैल, 2015 और 13 जुलाई 2015 के आदेशों के अनुसरण में कदम उठाने से प्रतिबंधित करने वाली निषधाज्ञा की एक रिट जारी करने, और उसे, आगे 25 अक्टूबर 2007 को बी. बी. सी. नं. 1/ 1993 में नामित टाडा कोर्ट, बॉम्बे द्वारा दी गई मौत की सजा के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा 2007 की आपराधिक अपील No.1728 में दिनांक 21 मार्च, 2013 के फैसले के माध्यम से की गई है, के लिए प्रार्थना की है, जब तक कि याचिकाकर्ता भारतीय संविधान अनुच्छेदों 72 और 161 के तहत उपचार सहित मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास परिवर्तित कराने के लिए उसके पास उपलब्ध सभी कानूनी उपायों को समाप्त नहीं कर देता है।

2. इससे पहले कि हम याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में किए गए तथ्यात्मक दावों और अप्रार्थियों द्वारा सामने रखा गया रुख और तत्व का विज्ञापन करें, हम इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में हुए घटनाक्रम को संदर्भित करने के लिये बाध्य हैं। रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, मामला दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया

था। इसके कुछ दिन के लिए सुना गया था। सुनवाई के बाद, अनिल आर. दवे, न्यायाधिपति ने निम्नलिखितव पारित कियाः

> "दोनों दलों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना।
>
> यह एक तथ्य है कि याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है और साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा दायर समीक्षा याचिका और उपचारात्मक याचिका को भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, महामहिम, भारत के राष्ट्रपति और महामहिम, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भीयाचिकाकर्ता द्वारा किए गए क्षमा के लिए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है, संभवतः याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के कारण।
>
> विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है याचिकाकर्ता की ओर से महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल को किया गया एक और आवेदन अभी भी लंबित है।
>
> यदि ऐसा है, तो सजा सुनाए जाने की तारीख से पहले आवेदन निष्पादित करने तक यह महामहिम के लिए खुला रहेगा, यदि महामहिम याचिकाकर्ता का पक्ष लेना चाहते हैं। उपचारात्मक याचिका के बारे में प्रस्तुतियाँ मुझे प्रभावित

नहीं करती क्योंकि वे अप्रासंगिक हैं और उनमें कोई तत्व नहीं है।

इन परिस्थितियों में, रिट याचिका को खारिज किया जाता है।"

3. कुरियन जोसेफ, न्यायाधिपति, अनिल आर. डेव, न्यायाधिपति से असहमत थे। असहमति का आधार जो कि उनके निर्णय से स्पष्ट है वह यह है कि उपचारात्मक याचिका जो कि 21 जुलाई, 2015 को इस न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा निष्पादित की गई थी, वह उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का आदेश XLVIII (संक्षेप में, नियम ') के नियम 4 के अनुसार आवश्यक रूप से गठित नहीं थी। उक्त नियमों के नियम 4 (1) और (2) और नियमों के आदेश I नियम 2 (के) में परिभाषित 'निर्णय' शब्द का उल्लेख करने के बाद विद्वान न्यायायाधिपति ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः

"यह भी ध्यान में रखना पूरी तरह से संदर्भ से बाहर नहीं हो सकता है कि समीक्षा याचिका में दिनांकित 09.04.2015 एक निर्णय शीर्षक के रूप में आदेश, स्पष्ट तौर पर, उच्चतम न्यायालय के नियमों के तहत 'निर्णय'की परिभाषा के संदर्भ में है। इस प्रकार, यह पाया गया है कि उपचारात्मक याचिका और वह भी एक व्यक्ति के जीवन से

निपटने के दौरान कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। उपचारात्मक याचिका में आदेश के मुखार पर एक स्पष्ट त्रुटि है। कानून के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

हालांकि विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान महान्यायवादी ने एक सुधारात्मक याचिका में उपलब्ध विभिन्न आधारों का उल्लेख किया, इस मामले में लिये गये मेरे विचार की प्रकृति में यह है कि स्वयं सुधारात्मक याचिका में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निर्णय नहीं लिया गया है, सबसे पहले उस दोष को ठीक करने की आवश्यकता है। अन्यथा, तत्काल मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन होता है।

अन्य बातों के साथ-साथ विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि यह रिट कार्यवाही में उठाया गया मुद्दा नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि न्याय करने के मार्ग में इस तरह की तकनीकीता को खड़ा होना चाहिए। जब यह न्यायालय संविधान के तहत व्यक्तियों के जीवन का रक्षक के रूप में एक ऐसी स्थिति पर ध्यान देने के लिए आया है जहाँ एक व्यक्ति को जीवन से वंचित करते समय कानून द्वारा स्थापित

एक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो होने वाले न्याय में कोई तकनीकीता रास्ते में नहीं आएगी। आखिरकार, कानून आदमी के लिए है और कानून कभी असहाय नहीं होता है और न्यायालय विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय जैसी उच्च संवैधानिक शक्तियों का भंडार शक्तिहीन नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में, मैं पाता हूँ कि उपचारात्मक याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। इसलिए, सुधारात्मक याचिका पर उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVIII के नियम 4 के तहत अनिवार्य आवश्यकताके संदर्भ में नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

मामले को ध्यान में रखते हुए, टाडा न्यायालय के दिनांकित 12.09.2006 निर्णय के अनुसार जारी किये गये मृत्यु वारंट, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.03.2013 द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, और जिसकी दायर समीक्षा याचिका को 09.04.2015 को पर खारिज कर

दिया गया है, पर उपचारात्मक याचिका में कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने तक रोक लगाई जाती है।

इस मामले पर निर्णय लेने के बाद, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि रिट याचिका विचार के लिए अदालत के सामने रखी जाए"

दो विद्वान न्यायाधिपतिगण के बीच मतभेद के आधार पर मामला हमारे समक्ष रखा गया है।

4. जैसा कि स्पष्ट है, न्यायाधिपति दवे ने रिट याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन उपचारात्मक याचिका के संबंध में की गई प्रस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया है और केवल यह राय दी कि वे अप्रासंगिक थी और उनमें कोई तत्व नहीं था। कुरियन जोसेफ, न्यायाधिपति जैसा कि उनके आदेश से पेटेंट है, ने उसी को विस्तार से संबोधित किया है और रिट याचिका को जीवित रखा है।

5. सबसे पहले, हम इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या उपचारात्मक याचिका को नियमोंका उल्लंघन करते हुए एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। चाहे यहाँ स्पष्ट किया गया हो, हम खुद को यह संबोधित करने से रोकते हैं और बचते हैं कि क्या ऐसा कोई आदेश हो सकता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सके। इस तरह से ऐसा लगता है कि, याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में इस तरह की

दलील नहीं ली गई थी। तथापि, विद्वान न्यायाधीश ने सोचा कि उस परविज्ञापन देना उचित था और उस पर ध्यान दिया और, इसलिए, संदर्भ उत्पन्न हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि उसका जवाब दें।

6. इस न्यायालय द्वारा उपचारात्मक क्षेत्राधिकार का निर्माण रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, 2002 (4) एस. सी. सी. 388 में संविधान पीठ के फैसले पर आधारित है। उक्त निर्णय से पहले, कुछ मामलों में निर्णयों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जाती थी। न्यायाधिपति कादरी के माध्यम से बहुमत ने बोलते हुए, यह राय दी कि अनुच्छेद 32 याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पोषणीय नहीं थी। यह स्थापित हो जाये, कानून का उक्त बयान उन विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया था जो पक्षों की ओर से उपस्थित हुए। हालांकि, यह यह भी माना गया कि उस संबंध में कुछ सिद्धांत विकसित होना चाहिये। उस आधार पर उपचारात्मक सिद्धांत विकसित किया गया था। उक्त सिद्धांत को विकसित करते समय, बहुमत ने निम्नलिखित रूप में नोट कियाः

> "48. ऊपर चर्चा किए गए मामलों में इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 142 के तहत अपने पहले के निर्णयों पर पुनर्विचार किया जो इस न्यायालय को पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिये विस्तृत शक्तियां

प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 129 के तहत इस न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्ति के दायरे का संकेत हम पहले ही ऊपर दे चुके हैं और संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्ति की सीमा तक भी विज्ञापित कर चुके हैं।

49. हमारे विचार में चर्चा का परिणाम यह है कि यह न्यायालय, अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के गम्भीर दुर्वहन का उपचार करने के लिए, अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है।

50. अगला कदम इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के तहत ऐसी उपचारात्मक याचिका पर विचार करने की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना है ताकि अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत उपचारात्मक याचिका की आड में मुद्दे की प्रक्रिया के तौर पर एक दूसरी समीक्षा याचिका दाखिल करने के लिए बाढ़ के द्वार न खोले जाएं। यह एक आम आधार है कि सिवाय इसके कि जब तक मजबूत कारण उपलब्ध न हों, न्यायालय को इस न्यायालय के ऐसे आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाले एक आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए जो पुनरीक्षण याचिका खारिज होने पर

अंतिम हो गया है। जिन आधारों पर ऐसी याचिका पर विचार किया जा सकता है उन सभी की गणना करना न तो उचित है और न ही संभव है।51. फिर भी, हम सोचते हैं कि एक याचिकाकर्ता पूर्व ऋण न्याय्यता की राहत का अधिकरी है यदि वह स्थापित करता है (1) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों उल्लंघन जिसमें वह लम्बित मुकदमे में एक पक्षकार नहीं था लेकिन फैसले ने उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला या, यदि वह लम्बित मुकदमे में पक्षकार था, तो उसे कार्यवाही नोटिस नहीं दिया गया था और मामला इस प्रकार आगे बढ़ा मानो उसके पास सूचना थी और (2) जहां कार्यवाहियों में एक विद्वान न्यायाधीश विषय-वस्तु के साथ अपने संबंध का खुलासा करने में विफल रहे या पक्ष एक पक्षपात की गुंजाइश की आशंका देते हैं और निर्णय याचिकाकर्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।"

7. हमने उपरोक्त अनुच्छेदों का उल्लेख इंगित करने के लिये किया है कि हालांकि बहुमत ने कहा है कि यह न तो उन सभी आधारों की गणना करना उचित और न ही संभव है जिन पर ऐसी याचिका पर विचार किया जा सकता है, फिर भी पीठ ने पूर्व ऋण न्याय्यता सिद्धांत निर्धारित किया और आगे दो आधारों की गणना की गई

8. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि उन आधारों के अलावा, अन्य आधार भी लिया जा सकता है। हम उसी पर रहने का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि हमें सीमित रूप से इस के संदर्भ में निपटने की आवश्यकता है, अर्थात, क्या उपचारात्मक याचिका का निर्णय नियमों के अनुसार विधिवत गठित पीठ द्वारा लिया गया था। इस संबंध में, यह समझना आवश्यक है कि रूपा अशोक हुर्रा मामले में क्या कहा गया है। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 52 इस प्रकार है –

> "याचिकाकर्ता, उपचारात्मक याचिका में, विशेष रूप से बचाव करता है कि उसमें उल्लिखित आधार पुनरीक्षण याचिका में थे लिये गये थे जिन्हे परिसंचरण में खारिज कर दिया गया था। उपचारात्मक याचिका में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणन शामिल होगा।"

9. पैराग्राफ 52 स्पष्ट रूप से बताता है कि उपचारात्मक याचिका में विशेष रूप से कहा जाएगा कि उसमें उल्लिखित आधार समीक्षा याचिका में लिया गया था और इसे परिसंचरण द्वारा खारिज कर दिया गया था। उपचारात्मक याचिका में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एक प्रमाणन होगा। पीठ का गठन नीचे पैराग्राफ 53 में किया गया है। उक्त अनुच्छेद का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"हमारा विचार है कि चूंकि यह मामला इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के पुनःपरीक्षण से सम्बंधित है, भले ही सीमित आधार पर पर, उपचारात्मक याचिका पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधिपतिगण और शिकायताधीन फैसला देने वाले न्यायाधिपतिगण, यदि उपलब्ध हैं तो, की पीठ को परिसंचरित होनी चाहिए। यह केवल तभी होता है जब इस पीठ के अधिकांश विद्वान न्यायाधिपतिगण ने सुनवाई करते हुए निष्कर्ष निकाला कि मामले को उसी पीठ (जहाँ तक संभव हो) के समक्ष सूचीबद्ध की आवश्यकता है जो उचित आदेश पारित कर सकती है।"

10. सम्विधान पीठ द्वारा जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, आदेश XLVIII की नियम स्थिति जो उपचारात्मक याचिका सेद निपटता है उस पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर उचित विचार की दृष्टि से, पूरे नियम को पुनः नीचे प्रस्तुत किया जाता है:

"1. उपचारात्मक याचिकाएँ न्यायालय के रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य में 1997 की रिट याचिका (सी) संख्या .509 के मामले में दिये गये निर्णय दिनांक 10 अप्रैल, 2002 द्वारा शासित होंगी।

2. (1) उपचारात्मक याचिका में, याचिकाकर्ता, विशेष रूप से बल देगा कि उसमें उल्लिखित आधार पुनरीक्षण याचिका में लिये गये थे और उन्हें परिसंचरण द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(2) एक सुधारात्मक याचिका एक वरिष्ठ अधिवक्ता के इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ होगी कि याचिका उपरोक्त मामले में वर्णित आवश्यकताएँ पूरी करती है।

(3) एक उपचारात्मक याचिका के साथ एक एदवोकेत ऑन रिकॉर्ड का इस आशय का प्रमाण पत्र कि विवादित मामले में यह पहली उपचारात्मक याचिका है।

3. उपचारात्मक याचिका समीक्षा याचिका में पारित निर्णय या आदेश की तारीख से उचित समयावधि के अंतर्गत दायर की जाएगी।

4. (1) उपचारात्मक याचिका पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधिपतिगण और वो न्यायाधिपतिगण जिन्होने शिकायताधीन निर्णय पारित किया, की पीठ, यदि उपलब्ध हो, तो को वितरित की जाएगी।

(2) जब तक कि अदालत द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, एक उपचारात्मक याचिका का निपटान परिसंचरण

द्वारा किया जाएग, बिना किसी मौखिक तर्क के लेकिन याचिकाकर्ता अपनी याचिका में पूरक के तौर पर अतिरिक्त लिखित तर्क दे सकता है।

(3) यदि वह पीठ जिसके समक्ष एक उपचारात्मक याचिका परिसंचरित की गई थी एक बहुमत से निष्कर्ष निकालती है कि मामले को सुनवाई की आवश्यकता है तब इसे जहाँ तक संभव हो उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

(4) यदि न्यायालय, किसी भी स्तर पर, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि याचिका बिना किसी योग्यता के और असंतोषजनक है, तो वह याचिकाकर्ता पर अनुकरणीय व्यय अधिरोपित कर सकता है।"

11. यह श्री राजू रामचंद्रन, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि न्यायाधिपति कुरियन द्वारा व्यक्त मत नियम के बिल्कुल अनुरूप है क्योंकि जिन न्यायाधिपतिगण ने समीक्षा याचिका की निपटान किया था वह उस पीठ के पक्षकार नहीं थे जिसने उपचारात्मक में निर्णय दिया था। उन्होंने नियम 4 (1) और नियम 2 (1) (के) में शब्दकोश खंड पर बहुत जोर दिया है जो " निर्णय "शब्द को परिभाषित करता है। वही इस प्रकार हैः

"2. (1) इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ आवश्यक न हो-

(के) 'निर्णय' में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी की डिक्री, आदेश, या सजा का निर्धारण शामिल है।"

12. सवाल, सार रूप में, यह होगा कि क्या "आदेश" शब्द जो कि आदेश । नियम 2 (1) (के) में निर्धारित "निर्णय" परिभाषा हिस्सा बनता है, का अर्थ यह होगा कि पुनरीक्षण में आदेश या मुख्य निर्णय में पारित निर्णय। रूपा अशोक हुर्रा (ऊपर) के अनुच्छेद 53 की अध्ययनपूर्ण पडताल और पूर्ववर्ती अनुच्छेद जिसे हमने यहाँ-ऊपर पुनः प्रस्तुत किया है, के द्वारा, उपचारात्मक याचिका पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधिपतिगण और शिकायताधीन फैसला देने वाले न्यायाधिपतिगण, यदि उपलब्ध हैं तो, की पीठ को परिसंचरित होनी चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि उसमें उपलब्धता का उल्लेख किया गया है। नियम संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार बनाया गया है।

13. हमें यह समझने की आवश्यकता है कि "शिकायताधीन निर्णय" शब्द का क्या अर्थ है। रूपा अशोक हुर्रा (ऊपर) सिद्धांत के अनुसार, दूसरी समीक्षा की अनुमति नहीं है। तथापि, एक उपचारात्मक याचिका न्याय की विफलता को रोकने और यह देखने के लिए कि उच्चतम न्यायालय में,

वहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं है, और पक्षपात नहीं है जो एक अलग तरीके से मूल रूप से प्राकृतिक न्याय का एक पहलू भी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विकसित की गई है। हम पुनरावृत्ति की कीमत पर दोहराते हैं, चाहे अन्य आधारों को लिया जा सकता है या नहीं, हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। समीक्षा का सिद्धांत जैसा कि जाना जाता है, मुख्य निर्णय को पुनः देखना परीक्षण करना है। यह कोई अछूता आधार नहीं है सौ चंद्र कांटे और अन्य बनाम शेख हबीब (1975) 1 एस. सी. सी. 674 में कृष्ण लायर, न्यायाधिपति द्वारा माना गया है। उक्त सिंद्धांत को कई प्राधिकरणों में दोहराया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जबकि यह न्यायालय एक उपचारात्मक याचिका के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, यह वास्तव में प्रमुख निर्णय/मुख्य फैसला है, जो विचाराधीन है।

14. उक्त निर्णय मुख्य निर्णय है और वास्तव में किसी मामले में दोषसिद्धि को अंतिम रूप देता है और पुनः परीक्षण का मामला अलग है। उपचारात्मक याचिका मुख्य निर्णय के खिलाफ दायर की जाती है जो वास्तव मे शिकायताधीन है। " शिकायताधीन " शब्दों को उस संदर्भ में समझना होगा जिसमें संविधान पीठ ने उपयोग किया है। संविधान पीठ के बहुमत की, जैसा कि हम समझते हैं, पूरी तरह से दृढ़ राय है कि समीक्षा की समीक्षा नहीं होगी और एक 32 अनुच्छेद पोषणीय नहीं होगा और इसलिए, ऐसी विधि का आविष्कार किया गया।

15. श्री राजू रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि उक्त मामले में विभिन्न याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ वकील हमेशा एक संयोजन सोचते थे। इसके विपरीत, श्री मुकल रोहतगी, विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि एक समामेलन हो सकता है, लेकिन तीन वरिष्ठतम न्यायाधिपतिगण को स्पष्ट रूप से न्यायपीठ के पक्षकार बनने के लिये कहा गया है और 'शिकायताधीन' निर्णय के न्यायाधिपतिगण को पक्षकार होना है और यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो कुछ अन्य न्यायाधिपतिगण को शामिल करना भारत के मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है; हालाँकि, यदि यह वरिष्ठतम न्यायाधिपतिगण द्वारा निपटा जाता है, जैसा कि इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधिपतिगण, तो आदेश अमान्य नहीं होगा। हमारी सुविचारित राय में, विद्वान महान्यायवादी श्री मुकुल रोहतगी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियाँ स्वीकृति योग्य हैं और, तदनुसार, हम मानते हैं कि इस न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधिपतिगण द्वारा तय की गई उपचारात्मक याचिका को न तो अमान्य या शून्य माना जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि पीठ के गठन में कोई अनियमितता हुई है। स्वीकार्य रूप से, वे न्यायाधिपतिगण जिन्होने निर्णय दिया था कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। यदि एक सिद्धांत के रूप में यह निर्धारित किया जाता है कि यदि जो न्यायाधिपतिगण कार्यालय छोद चुके न्यायाधिपतिगण की अनुपस्थिति में समीक्षा का निर्णय लेते हैं, उन्हें न्यायिक अनिवार्यता द्वारा

उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिये, तो यह उचित नहीं होगा। हम इस बात को लेकर पूरी तरह से सचेत हैं कि किसी निर्णय को एक कानून के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से किसी निर्णय को उचित दृष्टिकोण में समझा जाना चाहिए। हम फैसले पर जोर देते हैं क्योंकि नियम निर्णय के अनुरूप बनाए गए हैं और उसके विचलन में नहीं। अतः हम इस संबंध में कुरियन जोसेफ, न्यायाधिपति द्वारा व्यक्त इस दृष्टिकोण से असहमत हैं। श्री राजू रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने 'निर्णय' शब्द पर जोर दिया है क्योंकि समीक्षा याचिका की बर्खास्तगी को 'जजमेंट' के रूप में शीर्षक दिया गयाहै। नामकरण, हमारेविचार में, प्रासंगिक नहीं है। उदाहरण के लिए,हम कह सकते हैं, कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार कुछ मामलों में एक आदेश एक डिक्री की स्थिति ग्रहण कर सकता है और कुछ मामलों में एक डिक्री एक डिक्री नहीं हो सकती है। ऐसा कहने का उद्देश्य है कि चूंकि केवल इसलिए कि समीक्षा याचिका की बर्खास्तगी का नाम 'निर्णय' रखा गया है, यह 'शिकायताधीन निर्णय' की अवधारणा के दायरे और विस्तार के भीतर नहीं आएगा।

16. इस समय यह कहना समीचीन है कि कुरियन, न्यायाधिपति जैसा कि उनके निर्णय से स्पष्ट है, ने याचिका पर संविधान के अनुच्छेद 32 अनुसार विचार नहीं किया है, अपितु निर्देश दिया है कि उपचारात्मक याचिका पर अनिवार्य नियम के संदर्भ में नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। हम पहले ही इससे अपनी असहमति दर्ज कर चुके हैं। इसलिए, का

अगला चरण रिट याचिका के गुण-दोष पर चित्रण होना चाहिए। एक अनुक्रम के रूप में, इस न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधिपतिगण द्वारा उपचारात्मक याचिका की बर्खास्तगी को सही माना जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक अनियमितता से दूषित नहीं माना जाना चाहिए।

17. मुख्य याचिका पर आते हुए, उसमें की गई प्रार्थनाओं के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए, हमें कुछ तथ्यों का उल्लेख करना होगा क्योंकि वे बिल्कुल आवश्यक है। याचिकाकर्ता पर टाडा अदालत के समक्ष विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था जिसने उसे मौत की सजा सुनाई। अपील में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आरोपों, विभिन्न प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया और अंततः टाडा न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार के साथ सहमति जताई।

18. 21 मार्च 2013 को फैसला सुनाए जाने के बाद, समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की गई, जिसे 30 जुलाई, 2013 को परिसंचरण में खारिज कर दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका अस्वीकृति के बाद, याचिकाकर्ता के भाई सुलेमान ने, 6 अगस्त, 2013, संविधान के अनुच्छेद 72 (1) के तहत लाभ का दावा करते हुए को भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत अभ्यावेदन दिया। याचिकाकर्ता ने 7 अगस्त, 2013 को, केन्द्रीय कारागार, नागपुर के अधीक्षक को राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा याचिका की प्राप्ति के बारे सूचित करते हुए लिखा 2 सितंबर,

2013 को भारत सरकार ने दोषी की भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित दया याचिका को प्रक्रिया के अनुसार प्रधान सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र को भेज दिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 14 नवम्बर, 2013 को अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया और 30 सितंबर, 2013 को महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया। 10 मार्च, 2014 को राज्य सरकार की ओर से उक्त संचार की प्राप्ति पर, गृह मंत्रालय द्वारा तैयारमामले/दया याचिका का सारांश को गृह मंत्री के हस्ताक्षर के साथ भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 11 अप्रैल 2014 को, भारत के राष्ट्रपति ने याचिकाकर्ता की दया याचिका खारिज कर दी। उक्त अस्वीकृति 17/21.04.2014 को इस शर्त के साथ राज्य सरकार को सूचित कर दी गई थी, कि दोषी को सूचित किया जाए और तदनुसार, 26 मई, 2014 को याचिकाकर्ता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज होने के बारे में सूचित किया गया था।

19. जबकि उपरोक्त घटनाक्रम हुआ, अन्य अभियुक्तों के साथ याचिकाकर्ता ने मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य (2014) 9 एस. सी. सी. 737 में, ने उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के नियम 3 ऑर्डर XL को असंवैधानिक बताते हुए इसकी संवैधानिक वैधता पर हमला किया था। दिये गये तर्क का मुख्य आधार यह था कि पुनर्विचार याचिका की सुनवाई परिसंचरन में नहीं बल्कि खुले न्यायालय में होनी चाहिये और उन मामलों की सुनवाई जिसमें

मौत की सजा सुनाई गई है उच्चतम न्यायालय के यदि पाँच नहीं तो कम से कम तीन न्यायाधिपतिगण की पीठ द्वारा की जानी चाहिए। पक्षों के विद्वान वकीलों की सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने राय दी कि सभी मृत्यु दंड के मामलों में समीक्षा चरण में भी एक सीमित मौखिक सुनवाई होनी चाहिए।हम पैराग्राफ 39 और 40 को पुन; प्रस्तुत करना उचित समझते हैं, जैसा कि श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान महान्यायवादी ने एक पहलू पर जोर दिया है जिसका हम कुछ समय बाद संज्ञान लेंगे। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

> "39. अब से, उन सभी मामलों में जिनमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रहने के दौरान उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दिया गया है, केवल तीन माननीय न्यायाधिपतिगण की एक पीठ ही सुनवाई करेगी। यही कारण है कि ऊपर वर्णित सजा प्रक्रिया की अनिश्चितताओं को देखते हुए मौत की सजा प्राप्त अभियुक्त की यात्रा के अंतिम पडाव पर कम से कम तीन न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमागों को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि सभी म्रत्यु दंड मामलों को कम से कम 5 विद्वान न्यायाधीशों द्वारा सुना जाये। इसके अलावा, हम श्री लूथरा के इस आग्रह से सहमत हैं कि आम तौर पर समीक्षा याचिका को केवल

उसी पीठ द्वारा सुना जाए जिसने मूल रूप से आपराधिक अपील पर सुनवाई की थी। यह स्पष्ट रूप से इस कारण से है कि ताकि एक समीक्षा सफल हो, इसलिये अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटियाँ मिलनी चाहिये। यह स्वयंसिद्ध है कि जिन विद्वान न्यायाधिपतिगण ने गलती करने का आरोप लगाया अब उन्हें ही इस तरह की त्रुटि को सुधारने के लिए कहा गया है। इसलिए, हम श्री वेणुगोपाल की उस याचिका को कि मृत्युदंड के मामलों में समीक्षा चरण में दो अतिरिक्त न्यायाधिपतिगण को जोड़ा जाए खारिज करते हैं।

40. हम श्री जसपाल सिंह के तर्क पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि हम स्वीकार कर रहे हैं कि टाडा मामलों सहित मौत की सजा के सभी मामलों में एक सीमित मौखिक समीक्षा की जाए। रिट याचिका संख्या 39/2013 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जो बताया गया है हम उसे स्वीकार करते हैं और ऐसे सभी मामलों में 30 मिनट की एक बाहरी सीमा प्रदान करते हैं। जब हम पी. एन. ईश्वर लायर मामले की बात करते हैं जिस पर विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया था, हम पाते हैं कि उच्चतम न्यायालय के नियम में नवीन रूप से शुरू किये गये नियम 3 आदेश XL को

बरकरार रखने का कारण मूल रूप उच्चतम न्यायालय के कार्यभारसे गंभीर तनाव है। हम यह जोड़ सकते हैं कि वर्ष 1980 से तनाव में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, जैसा कि हमने ऊपर माना है, हम महसूस करते हैं कि जीवन का मौलिक अधिकार और मृत्यु की अपरिवर्तनीयता सजा अनिवार्य करती है कि म्रत्युदंड मामलों की समीक्षा चरण में मौखिक सुनवाई की जाए क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के रूप में इस तरह सुनवाई का आदेश है, और उच्चतम न्यायालय का कार्यभार गंभीर तनाव को स्थान नहीं दे मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पी. एन. ईस्वार अय्यर का मामला ही, दो दिलचस्प टिप्पणियों को देखा जाना है। पैरा 19 में, न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर कहते हैं कि " ..... स्थिति के न्याय के आधार पर प्रस्तुति लिखित या मौखिक हो सकती है"। और फिर से पैरा 25 में,विद्वान न्यायाधिपति ने कहा कि " समस्या वास्तव में यह खोजने की है कि अन्याय के जोखिम के बिना, किस श्रेणी के मामलों को मौखिक प्रस्तुति के बिना निपटाया जा सकता है।"

20. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ वर्ग के मामलों को सीमित मौखिक सुनवाई के लिए सुने जाने के लिए कवर किया गया। वही पैराग्राफ 46 में अभिनिर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार ह:

> "46. हम यह स्पष्ट करते हैं कि निर्णय में निर्धारित कानून, अर्थात।, जहाँ मृत्युदंड दिया जाता है, वहाँ समीक्षा याचिकाओं में सीमित मौखिक सुनवाई का अधिकार केवल लंबित समीक्षा याचिकाओं और भविष्य में दायर ऐसी याचिकाओं में लागू होता है। यह वहाँ पर भी लागू होगा जहाँ समीक्षा याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है लेकिन मौत की सजा को अब तक निष्पादित नहीं किया गया। ऐसे मामलों में, याचिकाकर्ता इस निर्णय की तारीख से एक महीना के भीतर अपनी समीक्षा याचिका को फिर से खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन, ऐसे मामले में जहां एक उपचारात्मक याचिका भी खारिज कर दी जाती है, इस तरह के मामलों को फिर से खोलना उचित नहीं होगा।"

21. इस तरह के मामलों में भी 30 मिनट की मौखिक सुनवाई दी जानी थी। श्री रोहतगी, विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि, कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अनुसार, ए मोहम्मद

आरिफ उर्फ अशफाक (ऊपर) मामलेमें निर्णय के अनुसरण में एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी और इसे लगभग 10 दिनों तक सुना गया। ऐसा प्रतीत होता है कि समीक्षा याचिका में पारित आदेश को पुनः प्रस्तुत किया जाए। यह इस प्रकार हैः

> "हमने पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और उत्तरदाता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार्पूर्वक सुना है। हमने समीक्षा करने की मांग वाले निर्णय का अध्ययन किया है और हम दोनों पक्ष की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार कर चुके हैं। जैसा कि अनुरोध किया गया है, हम दोषसिद्धि और सजा पर विवाद की विवेचना करने के लिए विचारण न्यायालय के निर्णय से भी गुजर चुके हैं। हमारे द्वारा उन्नत समीक्षा करने की मांग की। सभी याचिकाकर्ताओं में निर्णय तर्क दिए गए हैं जो है इसलिए, हमे अभिलेख या किसी अन्य आधार पर रूप से कोई त्रुटि नहीं मिली है जिससे हमारे अधिकार क्षेत्र की समीक्षा के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।"

इसलिए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है।

22. समीक्षा याचिका 09.04.2015 को खारिज कर दी गई थी। श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया है कि यह दूसरी समीक्षा याचिका है। इसके

विपरीत, श्री राजू रामचंद्रन का कहना था कि यह वास्तव में आरिफ में निर्णय के अनुसार समीक्षा याचिका को फिर से खोलना हुआ और इसलिए, इसे दूसरी समीक्षा याचिका नहीं कहा जा सकता है। जो भी हो, 09.04.2015 को विद्वान न्यायाधिपतिगण द्वारा समीक्षा याचिका अस्वीकृति के बाद, याचिकाकर्ता ने 22.05.2015 पर एक उपचारात्मक याचिका दायर की थी जिसे 21.07.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

23. इस मोड़ पर, हमें कुछ अन्य तथ्यों की सराहना करने के लिए एक मशीन समय में बैठने की आवश्यकता है। अपील का फैसला करने वाले न्यायाधिपतगण द्वारा समीक्षा याचिका खारिज किये जाने के बाद, 14.08.2013 पर मृत्यु वारंट जारी किया गया और दया याचिका 11.04.2014 को खारिज कर दी गई थी। 21.04.2015 को तीन न्यायाधिपतगण द्वारा उसे खुली सुनवाई देकर पुनर्विचार याचिका अस्वीकृति के बाद, याचिकाकर्ता को एक उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिये सूचित किया गया था और जैसा कि स्पष्ट है, उन्होंने एक उपचारात्मक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की शिकायत, जैसा कि जिसे श्री. राजू रामचंद्रन द्वारा काफी सराहा गया है, जिसे श्री अंधारुजिना और श्री ग्रोवर, वरिष्ठ वकील द्वारा पुनरुच्चारित किया गया है, जिन्होने कुछ संस्थानों के जरिये इस मामले में दखल दिया है, यह है कि प्रक्रियात्मक उल्लंघन हुआ है क्योंकि टाडा अदालत ने 30.07.2015 पर निष्पादन का निर्देश देते हुए

30.04.2015 को मौत का आदेश जारी किया था जबकि उपचारात्मक याचिका दायर की जानी बाकी थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ श्री अंधारुजिना और श्री. ग्रोवर की प्रस्तुति यह है कि यद्यपि टाडा न्यायालय ने 90 दिन का समय दिया था, अपूरणीय प्रक्रियात्मक अवैधता से ग्रस्त है और मृत्यु आदेश रद्द करने की मांग करती है। उन्होंने शत्रुघ्न चौहान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। [(2014) 3 एस. सी. सी. 1] और शबनम बनाम भारत संघ और अन्य। [2015 (7) स्केल 1] पर भारी निर्भर्ता रखी है। शत्रुघ्न चौहान का अनुच्छेद 241.7 श्री राजू रामचंद्रन, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ विद्वान वकील के समर्पण का गौरव है। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैः

> "241.7 कुछ जेल नियमावली में कैदी दया याचिका की अस्वीकृति की सूचना उसे और उसके परिवार प्रेषित करने और और उसकी फांसी की निर्धारित तिथि के बीच की न्यूनतम अवधि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कुछ जेल नियमावली में न्यूनतम 1 दिन की अवधि होती है, अन्य में एक न्यूनतम अवधि 14 दिन है। निम्नलिखित कारणों से यह आवश्यक है कि दया याचिका की अस्वीकृति के संचार की प्राप्ति और फांसी की निर्धारित तिथि के बीच 14 दिनों की न्यूनतम अवधि निर्धारित की जाए।:

(क) यह कैदी को मानसिक रूप से खुद को फांसी के लिये तैयार करने, भगवान के साथ अपनी शांति बनाने के लिए, और अन्य सांसारिक मामलों का निपटारा करने की उसकी वसीयत तैयार करने की अनुमति देता है।

(ख) यह कैदी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतिम और अंतिम बैठक करने की अनुमति देता है। यह कैदियों के परिवार के सदस्यों को को भी यात्रा की व्यवस्था करने के लिए अनुमति देता है जो जेल से किसी दूर के स्थान पर स्थित हो सकते है और उस कैदी से अंतिम बार मिल सकते है। फांसी की निर्धारित तिथि की पर्याप्त सूचना के बिना कैदियों के न्यायिक उपायों के लाभ के अधिकार को विफल कर दिया जाएगा और उन्हें उनके परिवार के साथ अंतिम और अंतिम बैठक करने से रोका जायेगा।"

24. यह श्री राजू रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आग्रह किया जाता है, कि इसका गैर-अनुपालन किया गया है मानो याचिकाकर्ता के लिए टाडा अदालत ने 90 दिनों का समय दिया हो, फिर भी राज्य द्वारा इसमें बिना अपरिमेय कारणों के कटौती की गई है। विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया है कि दया याचिका अस्वीकृति 26.05.2014 को प्रेषित की

गई थी। इसलिए, उक्त पैराग्राफ में दिए गए आदेश से वारंट दूषित नहीं होगा।

25. इस स्तर पर, हम यह ध्यान रखने के लिए बाध्य हैं कि श्री राजू रामचंद्रन विद्वान वरिष्ठ वकील के समर्पण का आधार, जिन्हें श्री अंधारुजिना और श्री ग्रोवर विद्वान वरिष्ठ वकील से भी समर्थन मिला है, कि उपचारात्मक याचिका खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता ने 22.07.2015 को महाराष्ट्र के राज्यपाल को दूसरी दया याचिका प्रस्तुत की और जब तक यह निस्तारित नहीं हो जाती, तब तक आदेश निष्पादित नहीं किया जा सकता है। बाद के चरण में हम उसी पर ध्यान देंगे। जहां तक निष्पादन की निर्धारित तिथि से 14 दिनों की अवधि के अनुपालन का संबंध है, यह समय सीमा को पूरा करता है।

26. अगला पहलू जिस पर याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रकाश डाला गया है वह यह है कि जिस तारीख को मृत्यु वारंट जारी किया गया था, टाडा अदालत ने उसे नहीं सुना, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। उक्त प्रस्तुतिकरण को मजबूत करने के लिए, उन्होंने हमें शबनम (ऊपर) में निर्णय के अनुच्छेद 11 की ओर आकर्षित किया है। उक्त अनुच्छेद को नीचे पुनरावृत किया है:

11) दूसरी ओर, जहाँ तक वर्तमान मामला संबंधित है, दया याचिका का चरण अभी तक नहीं आया है क्योंकि दोषियों को निर्णय दिनांक 15.05.2015 की समीक्षा की मांग करते हुए इस न्यायालय में समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर करने का अधिकार है जिसके अनुसार, दोनों अपराधियों की अपीलें खारिज कर दी गई थी। उन्होने हमारा ध्यान 'पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पी. यू. डी. आर.) बनाम भारत संघ और अन्य '(2014 की पी. आई. एल. संख्या 57810 28.01.2015 पर निर्णय लिया) नामक शीर्षक के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भी आकर्षित किया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रक्रिया को अनिवार्य किया है जो मृत्युदंड के निष्पादन से पहले होनी चाहिए। फैसले के उक्त हिस्से को नीचे निकाला गया हैः

> "हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है कि एक सभ्य समाज में, मृत्युदंड का निष्पादन ऐसे मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है, जिसमें कैदी को प्रक्रिया पालन की अनुमति और सूचना दिए बिना अंधेरे में रखा जाये। आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भारतीय दंड सन्हिता की धारा 413 और 414 के प्रावधान के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए और सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु वारंट जारी करने से पूर्व दोषी को

पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जो दोषी को अपने अधिवक्ताओं से परामर्श करने और कार्यवाही में प्रतिनिधित्व में सक्षम बनाएगा। दूसरा, वारंट के निष्पादन लिए सटीक तारीख और समय निर्दिष्ट करना होगा, न कि तारीखों की एक श्रंखला जो कैदी को अनिश्चितता की स्थिति में डाल देती है। तीसरा, फांसी के वारंट आदेश जारी करने और वारंट द्वारा नियत या नियुक्त तिथि पर फांसी देने के बीच एक उचित समयावधि का होना आवश्यक है ताकि दोषी उस वारंट के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने और फांसी के लिए निर्धारित तिथि से पहले उसके परिवार के सदस्य के साथ एक अंतिम बैठक करने का एक उचित अवसर प्राप्त कर सके। चौथा, फांसी वारंट की एक प्रति दोषी को तुरंत प्रदान की जानी चाहिए। पाँचवाँ, उन मामलों में जहाँ कोई दोषी कानूनी सहायता देने की स्थिति में नहीं है, कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये। यह आवश्यक प्रक्रियात्मक उपाय है जिसका पालन किया जाना चाहिये यदि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अर्थ और विषय-वस्तु पर संदेह नहीं है तो।"

27. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है, कि इस न्यायालय ने इलाहाबद उच्च न्यायालय की खंड पीठ के

कथन पर अनुमोदन की मुहर लगा दी है और इसलिये, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत यह एक कानून की घोषणा है। उनका आग्रह है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अध्याय 413 और 414 प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। वारंट जारी करने का समय दोषी को सुना जाना चाहिये। विद्वान महान्यायवादी, अपनी बारी में, यह तर्क दिया कि उक्त निर्णय 27.05.2015 को सुनाया गया थार जबकि इस मामले में वारंट 30.04.2015 को जारी किया गया था और यही कारण है कि विद्वान टाडा न्यायालय उसी सिद्धांत को लागू नहीं कर सकता था। मूल रूप से, श्री रोहतगी का निवेदन है कि उक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत को भावी रूप से लागू करना होगा। हमारी सुविचारित राय में, उक्त निर्णय में की गई अवधारणाओं को उक्त निर्णय के अनुच्छेद 20 और 21 से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं:

> " 20) इस प्रकार, हम मानते हैं कि निंदा योग्य कैदियों के पास भी गरिमा का अधिकार है और मृत्युदंड का निष्पादन दोषियों को सभी कानूनी उपचारों को पूरा करने की अनुमति दिए बिना मनमाने ढंग से, जल्दबाजी में और गुप्त तरीके से नहीं हो सकता है।
>
> 21) हम पाते हैं कि पी. यू. डी. आर. (ऊपर) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संविधान

के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है मृत्युदंड को निष्पादित करते हुए, उक्त प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है और अधिकारियों को शत्रुघ्न चौहान (ऊपर) के मामले में इस अदालत के निर्णय में निहित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है।"

28. इस प्रकार देखा जाए तो यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत एक कानून की घोषणा बन जाएगी और जब तक न्यायालय इसे भावी रूप से लागू करने के लिये नहीं कहता है यह हमेशा लागू रहेगी। लागू होता है। हालाँकि, यह भी देखा जाना चाहिए कि उक्त सिद्धांत के पीछे का उद्देश्य और मंशा क्या है और क्या यह इस मामले में मृत्यु वारंट जारी करने को प्रभावित करेगा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु वारंट जारी करने से पहले दोषी को पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए ताकि वह अपने अधिवक्ताओं से परामर्श कर सके और कार्यवाही में प्रतिनिधित्व कर सके। यह उद्देश्य होने के कारण, इसे तथ्यों की वर्तमान व्याख्या में देखा जाना चाहिये। इस मामले में, वारंट जारी होने के बाद, हालांकि, याचिकाकर्ता को 13.07.2015 को इसे प्रेषित कर दिया गया है, फिर भी उसने 22.05.2015 को उपचारात्मक याचिका दायर की थी और इसलिये, वह यह दलील नहीं दे सकता है कि उन्होंने कानूनी उपायों का लाभ नहीं उठाया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उपचारात्मक याचिका 21.07.2015 को खारिज कर दी गई है। हमारे विचार

में, इस मामले में उक्त शासनादेश के पीछे के उद्देश्य का अनुपालन किया गया है। हम थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं। शत्रुघ्न चौहान के मामले में, अपील खारिज होने के छह दिन बाद वारंट जारी किया गया। निस्सन्देह, ऐसे मामले में यह किसी भी सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। कहने की जरूरत नहीं है, वही सिद्धांत लागू होंगे लेकिन हस्तगत मामले में, उक्त सिद्धांत को यह कहने के लिए नहीं बढ़ाया जाए कि टाडा न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया जाना इनमें से प्रक्रिया के किसी एक पहलू के गैर-अनुपालन के आधार पर शून्य होगा। हम यह मानने के लिये इच्छुक हैं कि याचिकाकर्ता ने दोषसिद्धि से बचाव करने के लिए कई अवसरों का लाभ उठाया था और जैसा कि स्वीकार किया गया है जब पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई तब उसे दस दिन की पेशकश की गई।

29. हम पहले ही कह चुके थे कि हम दूसरी दया याचिका के पहलू से निपटेंगे जो 22.07.2015 को प्रस्तुत की गई है। श्री राजू रामचंद्रन, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया है, और श्री अंधारुजिना और श्री ग्रोवर ने उनका समर्थन किया कि दया याचिका का वर्णन प्रस्तुत करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अनुसार एक संवैधानिक अधिकार है। उक्त प्रस्तुतिकरण का समर्थन करते हुए, वे चौहान मामले के कुछ अंशों का उल्लेख करते हैं। उक्त मामले में यह कहा गया है कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। एक दोषी, उसकी दोष सिद्धि के बाद, किसी भी स्तर पर, क्षमा या माफी या अन्य राहत की

मांग करने के लिये जैसा कि उक्त अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया किया गया है, संवैधानिक प्राधिकारियों के पास अभ्यावेदन कर सकता है। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता के भाई ने भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता को यह पूरी तरह से पता था। उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित किया गया था कि भारत के राष्ट्रपति ने इसे11.04.2014 को अस्वीकार कर दिया है। एक तर्क उठाया गया है कि यह भाई था जिसने दया याचिका दायर की थी, न कि याचिकाकर्ता ने। उक्त तथ्य स्वीकार किया जाता है और अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, नागपुर को दिनांकित 07.08.2013 के पत्राचार से भी स्पष्ट होता है। ऐसी कोई गुहा नहीं हो सकती कि कुछ स्थितियों में दूसरी दया याचिका दायर की जा सकती है। यह श्री राजू रामचंद्रन द्वारा सामने रखा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त आधार लिये गये हैं जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होना शामिल है। यह आग्रह किया जाता है कि उन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत विचार किया जाए। श्री रोहतगी, विद्वान महान्यायवादी ने उसी पर विवाद किया है।

30. हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि दया याचिका से निपटना कार्यपालिका के हाथ में है। यह सच है कि, कुछ सीमित आधारों पर, शत्रुघ्न चौहान (ऊपर) के अनुसार, इसे चुनौती दी जा सकती है। हमें उस क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहली दया याचिका के खारिज हो जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती नहीं दी। उसने दया याचिका,

उसके संस्करण के अनुसार, 22.07.2015 को प्रस्तुत की थी। उस दया याचिका से कैसे निपटा जाएगा, हम उसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम केवल यह मानते हैं कि मृत्यु वारंट जारी करना प्रक्रिया के अनुसार है और हमें उसमें किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं मिलती है।

31. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उपचारात्मक याचिका जिसका निर्णय इस न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधिपतिगण द्वारा किया गया है, त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती है और टाडा अदालत द्वारा 30.04 2015 को जारी मृत्यु वारंट में दोष नहीं निकाला जा सकता है। नतीजतन, रिट याचिका, योग्यता के बिना, खारिज की जाती है।

देविका गुजराल

रिट याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक बृजेश कुमार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।